



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 420 राँची, बुधवार,

11 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 फरवरी, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) का पत्रांक- 8868, दिनांक 5 सितम्बर, 2006
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3412, दिनांक 7 जून, 2008, पत्रांक-6497, दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 संकल्प संख्या-4108, दिनांक 21 जुलाई, 2011, संकल्प संख्या-460, दिनांक 17 जनवरी, 2012, पत्रांक-6523, दिनांक 28 जुलाई, 2016, पत्रांक-5065, दिनांक 3 अप्रैल, 2017 एवं पत्रांक-115, दिनांक 3 जनवरी, 2018
3. राजस्व पर्षद, बिहार का पत्रांक-750, दिनांक 7 जुलाई, 2011
4. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-290, दिनांक 29 जून, 2015
5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक- 366, दिनांक 8 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-555/2014 का.-1345-- श्री रविन्द नाथ पण्डा, तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, प० चम्पारण, बेतिया, बिहार, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक-8868, दिनांक 5 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री पण्डा के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1- हनुमान सुगर मिल मोतिहारी के लिए निष्पादित लीज 34 वर्षों के लिए दिनांक 22 दिसम्बर, 1937 को निबंधित हुआ था। तदनुसार यह लीज 22 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हो गया। 22 दिसम्बर, 1971 से लीज नवीकरण नहीं हो सका है। सुगर मिल प्रबंधन ने 22 दिसम्बर, 1971 से लीज अवधि समाप्ति के पूर्व या बाद में लीज नवीकरण के लिए क्या पहल की है, इसपर व्यवस्थापक मौन है। लीज भूमि का रकबा 32.54 एकड़ है। इसके कई वर्षों से नवीकरण नहीं होने से राजस्व की क्षति हुई है। वर्तमान प्रबंधक ने सूचित किया कि लीज नवीकरण की दिशा में उनके स्तर से कोई कार्रवाई तब तक नहीं हुई, जब तक उन्हें राजस्व पर्षद्, बिहार का पत्रांक-3/20-29/95 दिनांक 25 फरवरी, 2000 दिनांक 6 फरवरी, 2000 को प्राप्त नहीं हो गया। स्पष्ट है कि 1970 से फरवरी 2000 तक लीज नवीकरण की दिशा में किसी स्तर पर किसी प्रबंधक ने (श्री आर०एन० पाण्डा सहित) कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि आर०एन० पाण्डा दिनांक 28 दिसम्बर, 1999 को अपने वर्तमान पद पर योगदान कर चुके थे।

श्री टी० दयाल, वरीय अधिवक्ता, बेतिया राज ने अपने पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2000 में यह अंकित किया कि पूर्व लेसी विलम्बकारी हथकण्डे अपना रहे हैं, उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि वे धारक लेसी नहीं हैं। बल्कि अतिक्रमाक हैं, उनके विरुद्ध लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। 31 दिसम्बर, 2000 को तिथि निश्चित की जाय। जब तक वे बकाये भुगतान कर सकें। श्री दयाल ने आगे अंकित किया कि लेसी ने लेसर को गुमराह करने का प्रयास किया है तथा यह तथ्य एवं डीड समाप्ति का तथ्य उसके निष्काषण के लिए पर्याप्त है। विद्वान अधिवक्ता ने साक्ष्य अमीन से नापी एवं नक्शा तैयार करने का परामर्श भी दिया। प्रबंधक बेतिया राज ने नापी करायी, परन्तु श्री टी० दयाल के पत्र में अंकित अन्य किसी भी बिन्दु का अनुपालन नहीं किया। राजस्व पर्षद् के ज्ञापांक-222, दिनांक 27 फरवरी, 2002 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई, जो अब तक अप्राप्त है।

आरोप सं०-2- एम०जे०सी०-51/81 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रामलखन सिंह महाविद्यालय बेतिया के परिसर के प्रश्नगत भू-खण्ड (खाता सं०-2 खेसरा सं०-390) मौजा करगहिया का अतिक्रमणकारियों से खाली कराने को कार्रवाई की गई तथा प्रबंधक बेतिया राज ने 15 दिसम्बर, 2001 को सांकेतिक कब्जा प्राप्त करने को लिखा। परन्तु बाद में उन्होंने

(प्रबंधक बेतिया राज ने) सूचित किया कि उन्हें जिला प्रशासन ने पूरी तरह से खाली कराये गये मकान आदि नहीं दिये थे ।

माननीय उच्च न्यायालय ने एम०जे०सी०-51/81 में दिनांक 31 जुलाई, 2002 के आदेश पारित करने की कृपा की कि “प्रतिपाल्य अभिकरण उपर्युक्त परिसर में अतिक्रमणों का विवरण प्रतिवादी जिला दण्डाधिकारी, बेतिया को उपलब्ध करायेगा, जो अतिक्रमणों को छान-बीन करने के बाद हटा देगा” व्यवस्थापक ने उपर्युक्त आदेश को अभिप्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व पर्षद् के समर्पित नहीं की तथा उनके स्तर से इस दिशा में कृत कार्रवाई अज्ञात है ।

आरोप सं०-3- अंचल अधिकारी बेतिया सदर तथा जिला प्रशासन पूर्वी चम्पारण ने बेतिया राज कार्यालय के सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया है, जिसमें बेतिया राज की भूमि पर दखलकारों की विवरणी है । अब बेतिया राज कार्यालय का दायित्व बनता है कि दोनों जिला प्रशासन को दखल की वैधानिकता या अवैधानिकता पर प्रतिवेदन समर्पित करें एवं नाजायज दखल के मामलों में अतिक्रमण वाद दाखिल करें । निरीक्षण टिप्पणियों व्यवस्थापक को अग्रसारित करने के बावजूद अब तक उनके स्तर से कृत कार्रवाई की जानकारी अप्राप्त है ।

आरोप सं०-4- भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, छपरा एवं बेतिया का मामला विगत कई वर्षों से लंबित है। छपरा में लेसी को निष्काशित करने का राजस्व पर्षद् का आदेश क्रियान्वित नहीं हुआ है । दोनों जिलों के समाहर्ताओं से व्यवस्थापक ने समन्वय पूर्वक मामलों का अनुश्रवण नहीं किया है ।

आरोप सं०-5- फैन्सी मेला बेतिया गैरमजरूआ मालिक खाता की जमीन पर लगता है, जो बेतिया महारानी का मकाननमय सहन था एवं घरे के अन्दर था । मामला अपर समाहर्ता बेतिया के न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है (आर०ए०-232/88) तथापि व्यवस्थापक के स्तर से मामले को अनुश्रवण की कोई सूचना नहीं है ।

आरोप सं०-6- दिनांक 10 अक्टूबर, 1999 को श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन सदस्य, राजस्व पर्षद् ने अंकित किया है कि जो दखलकारी लीज पर जमीन लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित दर पर जमीन दी जा सकती है । व्यवस्थापक द्वारा तथ्य एवं आंकड़े अब तक समर्पित नहीं किये जाने के कारण नीतिगत निर्णय नहीं हो पाया है ।

आरोप सं०-7- प्रबंधक बेतिया ने अपने पत्रांक-235, दिनांक 7 जुलाई, 1978 की कंडिका-2 में यह अंकित किया है कि 1955-56 में जमींदारी उन्मूलन के समय भूमि सुधार विभाग ने बेतिया राज के बिखरे हुए बकास्त बगीचों को अपने कब्जे में ले लिया । पुनः राजस्व विभाग ने अपने पत्रांक-7940, दिनांक 28 फरवरी, 1969 द्वारा सारी भूमि बेतिया राज को वापस लौटा दी परन्तु 1955 से 1969 के दरम्यान जब प्रश्नगत भू-खण्ड राजस्व विभाग के प्रबंधन में थे, बहुत से पेड़ कट गये और बहुत सी भूमि अतिक्रमित हो गई एवं कुछ भूमि पर अंचलाधिकारी ने विभिन्न व्यक्तियों

के साथ रसीद भी काट दी । 2300 एकड़ के कुल रकबा में बेतिया राज के दखल कब्जे में 812.29 एकड़ बतायी गयी । उपर्युक्त बीच की अवधि में बेतिया राज के दखल से निकल चुकी 1487.71 एकड़ भूमि बेतिया राज को वापसी के संबंध में व्यवस्थापक के स्तर से कुल कार्रवाई पर प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

आरोप सं०-8- व्यवस्थापक बेतिया राज को निदेश दिया गया था कि समय-समय पर विभिन्न व्यवस्थापकों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में जो भी प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, उसे अद्यतन एवं समेकित किया जाय । बेतिया राज से संबंधित प्रत्येक जिले को अलग-अलग अतिक्रमण विवरणी तैयार की जाय । प्रशासनिक एवं न्यायिक मामलों का अनुश्रवण किया जाय, ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके । अतिक्रमण विवरणी के लिए प्रपत्र भी विहित किया गया परन्तु अब तक कृत कार्रवाई की जानकारी व्यवस्थापक के स्तर से अप्राप्त है ।

आरोप सं०-9- दिनांक 10 मई, 2002 को अंचल कार्यालय, बेतिया सदर में बेतिया राज के जमीन पर हुए अतिक्रमण की समीक्षात्मक टिप्पणी में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर प्रबंधक बेतिया राज का अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है ।

आरोप सं०-10- दिनांक 9 मई, 2002 एवं 10 मई, 2002 को बेतिया राज से संबंधित न्यायिक विचाराधीन मामलों की समीक्षा में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर प्रबंधक, बेतिया राज का अनुपालन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है ।

आरोप सं०-11- बेतिया राज के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा समय-समय पर राज्य मुख्यालय में की गई, जिसका संदर्भ निम्नांकित है-

क्र०	बैठक की तिथि	अध्यक्षता	कार्यवाही निर्गत करने का संदर्भ	मंतव्य
1.	03.05.02	डा० सी० अशोक वर्द्धन, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार	446, दिनांक 08.05.02	बेतिया राज कोषांग की बैठक
2.	07.05.02	तदैव	449, दिनांक 08.05.02	बेतिया राज कोषांग
3.	14.05.02	श्री सी०एम० झा, सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार	486, दिनांक 16.05.02	-
4.	13.06.02	डा० सी० अशोक वर्द्धन, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार	691, दिनांक 25.06.02	बेतिया राज कोषांग

5.	06.08.02	श्री रमई राम माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	जाँच-930, दिनांक 27.08.02	-
6.	09.11.02	श्री सी०एम० झा, सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार	1239, दिनांक 19.11.02	-

उपर्युक्त बैठकों की कार्यवाहियाँ व्यवस्थापक, बेतिया राज को उपवर्णित संदर्भ के तहत निर्गत की गयी है परन्तु उनका बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

आरोप सं०-12- अंचल अधिकारी, बेतिया सदर ने पशु मेला खेसरा सं०-317 (बेतिया) पर व्यवस्थापक, बेतिया राज द्वारा अनियमित ढंग से अस्थायी बन्दोबस्ती की सूचना दी । प्रबंधक बेतिया राज द्वारा उपर्युक्त खेसरा पर मंत्री, राजस्व के एक वृत्तादेश के आलोक में गलत बन्दोबस्ती का आदेश पारित कर दिया । वृत्तादेश पर जब तक सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं होता है, तब तक इसे अंतिम आदेश मानना नियमों एवं परिपत्रों के प्रतिकूल है । जिला प्रशासन को निदेश दिया गया था कि उपर्युक्त बन्दोबस्ती के आदेश की जाँच करें । जाँच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है । इस संबंध में समाहर्त्ता, प० चम्पारण से कार्मिक विभाग सीधे जाँच प्रतिवेदन की माँग करते हुए अग्रतर कार्रवाई करना चाहेगा ।

आरोप सं०-13- बेतिया राज से संबंधित शील्ड बक्से, जो समाहरणालय, बेतिया के वज्रगृह में रखे गये हैं, का सत्यापन एवं समाहर्त्ता, बेतिया के सात पत्रों एवं प्रभार देने वाले अधिकारी के पत्रों व व्यक्तिगत सम्पर्क एवं दूरभाष सम्पर्क के बावजूद श्री आर०एन० पाण्डा, प्रबंधक बेतिया राज अब तक प्रभार ग्रहण नहीं कर सके हैं । इस संबंध में राजस्व पर्षद् के पत्रांक-1325(3) दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 के द्वारा कार्मिक विभाग को भी सूचित किया गया एवं श्री पाण्डा के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया । शील्ड बक्से के सत्यापन एवं प्रभार श्री पाण्डा द्वारा नहीं लिया जाना उनके स्तर से बेतिया राज के हित में घोर लापरवाही का द्योतक है ।

आरोप सं०-14- व्यवस्थापक, बेतिया राज ने बेतिया राज के शीश महल स्थित कला कृतियों सामग्रियों को शीश महल सहित बिहार सरकार द्वारा स्थापित बेतिया संग्रहालय में स्थानान्तरित करने से संबंधित हस्तांतरण डीड पर्षद् के आदेश के बावजूद अब तक उपलब्ध नहीं कराया है ।

आरोप सं०-15- ग्राम चिकनी के निवासियों ने राजस्व पर्षद् में बेतिया राज की जमीन मकान पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण का आरोप लगाया था । साथ ही पत्रकारों ने बेतिया राज प्रबंधक एवं फार्म मैनेजर की मिलीभगत से बेतिया राज की जमीन के धड़ल्ले से बेचे जाने की सूचना राजस्व

पर्षद् को दी थी, जिसपर राजस्व पर्षद् के पत्रांक-792, दिनांक 22 जुलाई, 2002 के द्वारा व्यवस्थापक, बेतिया राज से स्पष्ट प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो अब तक अप्राप्त है।

आरोप सं०-16- व्यवस्थापक बेतिया राज द्वारा वर्ष 1977-78 से 2000-2001 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन नहीं किया गया है। लेखापाल द्वारा रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्हें राजस्व पर्षद् की ओर से अनेक पत्र भेजे गये हैं तथापि व्यवस्थापक के स्तर से किसी अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना नहीं है।

आरोप सं०-17- लाल बाजार बेतिया नगरपालिका वार्ड नं०-14 के होल्डिंग सं०-347, खेसरा सं०-5667 एवं 5668 को बेतिया राज की जमीन पर किरायादार द्वारा खपड़पोश मकान को तोड़कर दो मंजिला पक्का मकान निर्मित करने की सूचना श्री वेनो प्रसाद नामक व्यक्ति ने राजस्व पर्षद् में दी, जिसपर पर्षदीय पत्रांक-1314, दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा आवश्यक कार्रवाई का निदेश व्यवस्थापक, बेतिया राज को दिया गया। कृत कार्रवाई पर प्रतिवेदन अप्राप्त है, जो व्यवस्थापक की शिथिलता एवं मिलीभगत की ओर संकेत करता है।

आरोप सं०-18- मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना ने मंझौलिया अन्तर्गत लाल सरैया के भूमिहीनों का आवेदन राजस्व पर्षद् में दिया, जिस पर पर्षदीय पत्रांक-1329, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 द्वारा व्यवस्थापक, बेतिया राज से प्रतिवेदन की माँग की गयी। प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। यह इनकी शिथिलता एवं मिलीभगत की ओर संकेत करता है।

आरोप सं०-19- श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, पत्रकार द्वारा अतिक्रमण की सूचना राजस्व पर्षद् में प्राप्त हुई। इस पर पर्षदीय पत्रांक-..... व्यवस्थापक से प्रतिवेदन की माँग की गयी है, जो प्रतिक्रिया है।

आरोप सं०-20- समय-समय पर समाहर्ता, प० चम्पारण ने वर्तमान व्यवस्थापक के विरुद्ध प्रतिवेदन राजस्व पर्षद् को समर्पित किया है, जिस पर व्यवस्थापक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं उसे समाहर्ता को मंतव्य हेतु प्रेषित किया गया, तथापि समाहर्ता का मंतव्य अब तक अप्राप्त है। इस संबंध में उन्हें कई स्मार दिये गये हैं। वर्णित परिस्थिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सीधे समाहर्ता से मंतव्यों की माँग करना चाहेगा।

आरोप सं०-21- बेतिया स्थित साठी फार्म के मामले में सूरजमल राजगडिया के उत्तराधिकारियों के शिनाख्त करने एवं दखलकारों पर अतिक्रमण वाद के तहत सुदृढ़ कार्रवाई करने में व्यवस्थापक विफल रहे।

आरोप सं०-22- भवानीपुर की जिरात पूर्वी चम्पारण के प्रसंग में 1997 में अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण माना। श्री टी० दयाल, राज के अधिवक्ता ने परामर्श दिया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता की वैधानिक स्थिति की जानकारी दी जाय पर व्यवस्थापक ने कोई कार्रवाई नहीं की।

आरोप सं०-23- मीना बाजार बेतिया में माननीय उच्चतम न्यायालय में पराजय के बाद व्यवस्थापक ने मामला सिविल कोर्ट ले जाने के लिए आवेदन दायर नहीं किया ।

आरोप सं०-24- श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन माननीय सदस्य, न्यायालय ने विचाराधीन मामलों की अद्यतन सूची बनाने का निदेश दिया था । व्यवस्थापक द्वारा आज तक अनुपालन नहीं किया गया ।

आरोप सं०-25- वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बेतिया राज के स्वामित्व में स्थित फलकारों की बन्दोबस्ती की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि कुल 31 (इकतीस) फलकारों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी । इस संबंध में अपर समाहर्ता, पश्चिमी चम्पारण ने आरोप लगाए हैं कि अबन्दोबस्त रैयतों से जो भी राशि प्राप्त हुई है, उसे आपस में बंटवारा कर दिया गया है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3412, दिनांक 7 जून, 2008 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में श्री पण्डा द्वारा पत्रांक-34, दिनांक 25 सितम्बर, 2008 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6497, दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 द्वारा राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी है । राजस्व पर्षद्, बिहार का पत्रांक-750, दिनांक 7 जुलाई, 2011 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री पण्डा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

अतः समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-4108, दिनांक 21 जुलाई, 2011 द्वारा श्री पण्डा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री एन०एन० पाण्डेय, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् संकल्प संख्या-460, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा इनके स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-290, दिनांक 29 जून, 2015 द्वारा श्री पण्डा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया ।

श्री पण्डा के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित कुल-25 आरोपों में से 17 आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री पण्डा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य के समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 5 वर्षों के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन से राशि कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया । उक्त प्रस्तावित दण्ड को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा

अनुमोदित किये जाने के उपरांत प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6523, दिनांक 28 जुलाई, 2016 द्वारा श्री पण्डा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

उक्त पत्र का तामिला नहीं होने पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री पाण्डा को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का अनुरोध किया गया, परंतु इनका पूर्ण उत्तर अप्राप्त रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक-5065, दिनांक 3 अप्रैल, 2017 द्वारा स्मारित किया गया। फिर भी इनका उत्तर अप्राप्त रहा।

श्री पाण्डा का पूर्ण उत्तर अप्राप्त रहने के कारण पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 5 वर्षों के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन से राशि कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-115, दिनांक 3 जनवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 366, दिनांक 8 फरवरी, 2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः, श्री रविन्द नाथ पण्डा, तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, प० चम्पारण, बेतिया, बिहार, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 5 वर्षों के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन से राशि कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
